लोकप्रियता की ढलान पर शेख हसीना

लोकप्रियता एक ऐसा असाधारण गुण है जो उस समय शासकों से दूर भागने लगती है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रही हैं। वहां सरकार का भाव ऐसे समय में नीचे आया है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लोगों ने उसे भारी बहुमत से विजयी बनाया था। लेकिन तीन साल की सत्ता के बाद लोग यह तेजी से महसूस करने लगे हैं कि भले ही उनके शासन को 'कुशासन' न कहा जाये, यह एक अकुशल शासन जरूर है और इसने लोगों का जीवन सिर्फ दयनीय बनाया है।

बांग्लादेश की सरकार ने न केवल अपनी चमक खो दी है बल्कि वह विश्वास भी जो उसे कभी हासिल था। लोगों ने उससे यह उम्मीद की थी कि वह नतीजा देगी। लेकिन उनके सामने ऐसा कुछ नहीं है जिससे वे उसकी उपलब्धि के रूप में पहचान सकें। उदाहरण के तौर पर, उसने बिजली का वायदा किया था और काफी हद तक उसे निभाया भी। बैंकों से उधार लेकर महंगे दामों पर बिजली की सप्लाई की। लेकिन लोग तो बड़े-बड़े पावर-स्टेशन खड़े होने की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत की ओर से भी जो आश्वासन दिये गए थे वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे।

सीमित संसाधनों के बीच गरीबी दूर करना सदैव एक चुनौती होती है लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास करती भी दिखाई नहीं दे रही है। उसने जो कुछ किया है उसी से संतुष्ट दिखाई दे रही है और आलोचकों को यह कह कर रोक देती है कि उनके बिजली कनेक्शन काट दो जो एयर कंडीशन में बैठकर बिजली की कमी की शिकायत कर रहे हैं। जब अखबार और टेलीविजन ने बिजली की कमी का सवाल उठाया तो उसने यही बयान दिया।

बेशक, हसीना ने आतंकवाद पर काबू पाया है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि उनका राष्ट्र बांग्ला भाई जैसे कट्टरपंथियों की दया पर निर्भर नहीं है। हसीना ने सोच-समझ कर बांग्लादेश नेशननिलस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया द्वारा खोती जा रही राजनीतिक जमीन वापिस हासिल कर ली है। हसीना को यह श्रेय भी मिलना चाहिए कि जो भारत विरोधी भावना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फैलाई थी वह करीब-करीब गायब हो चुकी है। और उसने पूर्वात्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत को रास्ता देने का एकतरफा कदम उठाया। लेकिन भारत समर्थक लोगों को यह सवाल चिंतित कर देता है कि हसीना ने जिस हद तक किया है क्या भारत ने बदले में वैसा ही किया है? बांग्लादेश को ऑफर किये गये कर्ज भारतीय आयातों और तकनीकी ज्ञान की शर्तों से बंधे हैं। क्षेत्रों के हस्तान्तरण की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जबकि कुछ सप्ताह पहले ढाका यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह इस पर राजी हो गये थे (क्षेत्रों के हस्तान्तरण को लेकर असम बेहद गुस्से में है)।

भारत के खिलाफ ज्यादा निराशा तीस्ता नदी के जल के बंटवारे से इंकार को लेकर है। उन्हें लग रहा है कि नई दिल्ली और कोलकाता के बीच राजनीतिक तकरार के कारण उन्होंने इसे खो दिया (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल के बंटवारे के फार्मूले पर सहमत थीं लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना मन बदल लिया और नदी आयोग की नियुक्ति कर दी)। कुछ लोगों को यह विश्वास है कि तीस्ता का पानी भी उन्हें उसी तरह मिल जायेगा जिस तरह फरक्का बराज की जलधारा तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के उदार रवैये के कारण आ गई थी। यह ममता पर निर्भर करता है क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार अपने अस्तित्व के लिये उनके लोकसभा सदस्यों पर इतना निर्भर है कि वह तीस्ता के मुद्दे पर कोई दबाव नहीं बना सकती।

इस चोट पर असर कम ही हो रहा था कि मणिपुर में बराक नदी पर तिपाईमुख बांध बनाने को लेकर भारत सरकार व मणिपुर की राज्य सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबर प्रकाश में आ गई। बीबीसी की यह खबर पहले पुष्ट नहीं थी। लेकिन बाद में दूसरे स्रोतों ने इसका समर्थन किया। मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के महीने भर बाद २३ अक्टूबर पर इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ढाका को इस बात की चोट लगी कि दिल्ली व उसके बीच जो समझ बनी थी उसका उल्लंघन हुआ है। दिल्ली ने उन्हें यह समझ दी थी कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे ढाका के हित प्रभावित हों।

नई दिल्ली ने खबर आने के ७२ घंटे बाद यह स्पष्टीकरण दिया कि बांध बाढ़ रोकने के लिये है और यह जलधारा को नहीं मोड़ेगा। इससे बांग्लादेश के लोगों की भावना कम नहीं हुई। बिना बताये हस्ताक्षर का होना भी परस्पर विश्वास का उल्लंघन था। यह शिकायत का एक अलग मुद्दा है कि बांध माहौल बिगाड़ सकता है। भारत की ५२ नदियां बांग्लादेश की ओर बहती हैं। मेरी राय में नई दिल्ली ढाका को यह साफ समझ दे कि उन्हें बिना बताये बड़ी नदियों को छुआ नहीं जायेगा।

दबाव झेल रही हसीना ने कुछ और प्रतिष्ठा गंवाई है। भारत के साथ दोस्ती के उसके प्रयास को दुत्कार मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि तीस्ता जल और तिपाईमुख दो साल बाद हो रहे चुनाव में उसके वोट में कटौती लायेंगे और इसका फायदा खालिदा जिया को मिलेगा जो आराम से बैठी हैं और पहले ही तरह बयान नहीं दे रही हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश किसी गेंद की तरह है जो कभी हसीना तो कभी खालिदा के पाले में जाती रहे? उसके साथ ऐसा उसी समय से होता आया है जब ४० साल पहले वह दूर बैठे पाकिस्तान से आजाद हुआ था। बांग्लादेश के लोग असहाय व हताश महसूस करते हैं। वे खुलकर सैनिक शासन की बात करने लगे हैं। सेना भी हसीना सरकार की मनमानी नियुक्तियों व स्थानान्तरणों से खुश नहीं है। तीन साल पहले कामचलाऊ सरकार को उनका समर्थन कोई काम नहीं आया। सेना न तो प्रशासन को साफ-सुथरा कर पाई और न ही दो बेगमों का कोई विकल्प खड़ा कर पाई।

बेशक, हसीना ने आतंकवाद पर काबू पाया है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि उनका राष्ट्र बांग्ला भाई जैसे कट्टरपंथियों की दया पर निर्भर नहीं है। हसीना ने सोच-समझ कर बांग्लादेश नेशननिलस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया द्वारा खोती जा रही राजनीतिक जमीन वापिस हासिल कर ली है। हसीना को यह श्रेय भी मिलना चाहिए कि जो भारत विरोधी भावना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फैलाई थी वह करीब-करीब गायब हो चुकी है। और उसने पूर्वात्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत को रास्ता देने का एकतरफा कदम उठाया। लेकिन भारत समर्थक लोगों को यह सवाल चिंतित कर देता है कि हसीना ने जिस हद तक किया है क्या भारत ने बदले में वैसा ही किया है? बांग्लादेश को ऑफर किये गये कर्ज भारतीय आयातों और तकनीकी ज्ञान की शर्तों से बंधे हैं। क्षेत्रों के हस्तान्तरण की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जबकि कुछ सप्ताह पहले ढाका यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह इस पर राजी हो गये थे

भारत के साथ दोस्ती बांग्लादेश के लोगों के लिए तिनके का एक सहारा था जिसे उन्होंने थाम लिया। आज वे सवाल कर रहे हैं कि भारत के साथ उनका कोई भविष्य भी है या नहीं? चीन उन्हें पाटने की बेहद कोशिश कर रहा है लेकिन वह उनकी पसंद नहीं है क्योंकि पेईचिंग ना तो लोकतांत्रिक है और न ही विविधता में विश्वास करने वाला है। बंग-बंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही बांग्लादेश इन दो सिद्धांतों पर पूरी तरह टिका हुआ है।

बांग्लादेश के लोग ये जरूर चाहेंगे कि वे अपनी बुद्धि से अपना देश बनायें। क्या उनके पास समय है? क्या उन्हें ऐसा करने दिया जायेगा?

भारत की तरह बांग्लादेश में भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध फैली हुई है। और वहां भी देशवासी इस बात से बेचैन हैं कि शीर्ष पर बैठे लोग सहूलियतें पाने और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए सत्ताधीशों से दोस्ती करने में लगे हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार के भय के कारण विश्व बैंक ने भी पद्मा पुल बनाने के लिए दी जा रही सहायता रोकने की धमकी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले को अपने हाथ में लिया है तो इसके सुलझ जाने के आसार बने हैं। इससे यह आमधारणा ही रेखांकित हुई है कि कुछ मंत्रियों की हैसियत बाकी से ज्यादा है।

हसीना को इस सबकी ज्यादा परवाह नहीं है क्योंकि लोकप्रियता का तेज नशा उसे वास्तविकता की ओर जाने से रोक रहा है। उसे लग रहा है कि कुछ अखबार उसकी अच्छी छवि खराब करने में लगे हैं वह यह नहीं समझतीं कि अखबार का सर्कुलेशन उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर होता है। परिस्थितियों की गलत रिपोर्ट या व्याख्या करने के बाद कोई अखबार आगे का स्थान बनाये नहीं रख सकता। लेकिन कम्युनिस्टों की तरह वह पाखंडियों को तो माफ करती है लेकिन आलोचकों को नहीं।